सशक्तीकरण ही सामर्थ्य...

12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

विषय-सूची

अध्याय 1
नारी नेतृत्व में विकास की नई परिभाषा
पेज 6

अध्याय 2
सशक्त युवाः विकसित भारत के सारथी
पेज 23

अध्याय 3
समर्थ किसान, समृद्ध राष्ट्र
पेज 38

अध्याय 4
वंचितों का विकास, राष्ट्र की सशक्त धारा
पेज 53

सशक्तीकरण ही सामर्थ्य...
अमृत काल में हों सभी सशक्त

"मेरे लिए तो जो गरीब हैं, वंचित हैं, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब वीआईपी है। देश की हर माता-बहन-बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान वीआईपी है। देश का हर युवा वीआईपी है।"

जब राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व की सोच इतनी व्यापक हो, तो सशक्तीकरण की यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से शुरू हुई यह धारा आज एक प्रवाह बन चुकी है।

एक दौर था जब देश की महिलायें हों या युवा, वंचित हो या किसान, सभी को नियति के भरोसे छोड़ दिया गया था। ऐसे में 12 वर्ष पूर्व जब राष्ट्र का नेतृत्व बदला, तो नीति-निर्माण की सोच में भी नयापन आया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विराट संकल्प लिया और उन वर्गों की ओर विशेष ध्यान दिया, जिन्हें कोई नहीं पूछता था। उन्होंने इन वर्गों को न केवल पूछा, बल्कि पूजा।

वे जिन चार स्तंभों को विकसित भारत का आधार बताते हैं, इन्ही चार स्तंभों को मिलाकर बना है **GYAN**- यानि गरीब, युवा शक्ति, अन्नदाता किसान, और नारी शक्ति।

"आज देश का लक्ष्य है- विकसित भारत, सशक्त भारत! हमें विकसित भारत के सपने को पूरा किए बिना नहीं रुकना है। मुझे विश्वास है, हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा, अपने कंधों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा।"

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

नारी शक्तिः विकास की धुरी

एक समय था जब महिला सशक्तीकरण को सीमित दायरे में देखा जाता था और देश में तीन तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियां थीं।

आज महिला सशक्तीकरण केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं, बल्कि संवेदनशील सोच और आर्थिक विकास की अनिवार्यता बन चुका है।

सेना हो या स्टार्टअप, ओलंपिक-पैरालिंपिक हो या शोध- नए भारत में बेटियां हर क्षेत्र में परचम फहरा रही हैं। तीन तलाक इतिहास बन चुका है।

IMF के अनुसार, महिलाओं की पुरुषों के बराबर भागीदारी से भारत की **GDP**

27% तक बढ़ सकती है।

इसी भावना के साथ नारी के नेतृत्व में विकास का मंत्र आज राष्ट्र की नीति का आधार बन गया है। केंद्र सरकार लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है।

नारी शक्ति के बिना राष्ट्र की समृद्धि अधूरी है, यही आज भारत की नीति का मूल मंत्र है।

युवा शक्तिः अमृत पीढ़ी

भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जड़ें मजबूत कीं, कौशल विकास ने नया मार्ग खोला है।

स्टार्टअप से यूनिकॉर्न तक, जमीन से अंतरिक्ष तक, युवा पीढ़ी हर सपने को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री का यह उद्घोष- "**यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है**" - युवाओं को समर्पित विकसित भारत का मंत्र है।

किसानः आत्मनिर्भरता की नींव

किसान सशक्तीकरण आज आत्मनिर्भर भारत की नींव है। लागत से डेढ़ गुना **MSP** सुनिश्चित हुई है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य आगे बढ़ा है। कृषि इंफ्रा फंड और **e-NAM** जैसे डिजिटल मंच किसानों को सशक्त बना रहे हैं। यह केवल वादे नहीं, बीते 12 सालों की सच्चाई है।

श्रीअन्न (**Millets**) को वैश्विक पहचान मिली। भारत पहली बार कृषि निर्यात में दुनिया के टॉप-10 देशों में शामिल हुआ।

"राष्ट्रपति पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।"

-द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति का प्रथम संबोधन

वंचितों को वरीयताः गरिमामय जीवन

2014 से पहले करोड़ों लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। पहली बार एक विशेष अभियान के जरिए सरकार खुद चलकर उन तक पहुंची है, जिन्हें दशकों से किसी ने नहीं पूछा था। प्रधानमंत्री मोदी ने शासन की शुरुआत में ही 'वंचितों को वरीयता' का सिद्धांत अपनाया।

बीते 12 साल में उनके जीवन में बदलाव आया है और गरिमामय जीवन पाकर वे राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं।

SC-ST समाज के लिए बजट साल-दर-साल बढ़ा है। शिक्षा, रोजगार व उद्योग में इनकी भागीदारी बढ़ी है।

स्वर्णिम भारत की यात्रा जारी है

बीते 12 वर्ष गरीब, नारी, युवा और किसानों के सशक्तीकरण का ऐतिहासिक कालखंड बने हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलकर सरकार सभी को विकास का भागीदार बना रही है।

अब विकसित भारत के संकल्प के साथ जन-जन के सशक्तीकरण की यह धारा अविरल बह रही है।

अध्याय 1

नारी नेतृत्व में विकास की नई परिभाषा

पीएम उज्ज्वला योजना
से धुंआ मुक्त हुई रसोई

लगभग **11** करोड़

गरीब महिलाओं को मिला एलपीजी कनेक्शन

- महिलाओं को श्वास संबंधी रोग में 20 प्रतिशत की आई कमी
- स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं भी कम हुईं
- घर के कामकाज में समय की होने लगी बचत
- बच्चों और घर के कामकाजी पुरुषों को समय पर भेजने में मिली मदद
- वनों की कटाई पर नियंत्रण हुआ, पर्यावरण की सुरक्षा भी बढ़ी
- वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक ने महिलाओं के सशक्तीकरण में सबसे बड़ी पहल माना

योजनाओं से नारी जीवन में सुगमता का नया युग

पीएम जन धन योजना
से हो रहा आर्थिक सशक्तीकरण

32+ करोड़ महिलाओं के खुले बैंक खाते

- जनधन के रूप में देश के हर नागरिक के पास बैंक खाता
- गरीबों तक सरकार की सब्सिडी सीधे पहुंच रही
- जैम ट्रिनिटी (जनधन, आधार और मोबाइल) का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मिली मदद
- वित्तीय सुरक्षा हुई सुनिश्चित, समावेशी विकास और सशक्तीकरण की बड़ी पहल

3+ करोड़

महिला किसान
पीएम-किसान योजना
से लाभान्वित

- आर्थिक सहायता मिलने से खेती हुई आसान
- अब उधार मांगने की जरूरत नहीं

91+ लाख

स्वयं सहायता समूहों

से स्वावलंबी हो रहीं

10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं

- महिलाओं की आजीविका-स्वरोजगार का महत्वपूर्ण साधन बना
- लखपति दीदी बनने में सहायक
- कृषि, बीमा सखी आदि के रूप में दे रहीं योगदान

पीएम सुकन्या समृद्धि योजना

सुरक्षित हो रहा बेटियों का भविष्य,खुले लगभग

4.5+ करोड़ **बैंक खाते**

- बेटियां आर्थिक रूप से हुईं समृद्ध
- उच्च शिक्षा और विवाह में खर्च की चिंता से मुक्ति
- बदली सोच, लिंगानुपात में भी हुआ सुधार

पीएम मुद्रा योजना

से सपने हो रहे साकार, महिला उद्यमियों को मिला

₹16+

लाख करोड़ का लोन

- सस्ते दर पर गारंटी मुक्त और आसान लोन की सुविधा
- हर 3 में से 2 लोन महिलाओं को मिले
- लगभग 70 % लोन महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को मिले

3+ करोड़

लखपति दीदी

बन रहीं ग्रामीण भारत की नई पहचान

- 2030 तक 3 करोड़ और नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

3+ करोड़

महिला-नेतृत्व वाले एमएसएमई

दे रहे देश की प्रगति में अपना योगदान

7.3+ करोड़

गर्भवती महिलाओं की

पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान

के तहत हुई जांच

- उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया जैसे रोगों की समय पर पहचान
- प्रसव से पहले हाई-रिस्क केस चिह्नित
- मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी
- SDG की दिशा में मजबूत कदम

पीएम मातृ वंदना योजना

के तहत गर्भवती महिलाओं को मिली

₹20,000+ करोड़

की आर्थिक सहायता

17+ करोड़ महिला श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत

- राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल होने से मिली नई पहचान
- सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जुड़ना हुआ आसान
- ब्रिक्स देशों में महिला श्रम भागीदारी वृद्धि में भारत अग्रणी

महिलाओं के स्वास्थ्य और सुविधा का ख्याल

जन औषधि केंद्रों में 1 रुपये में मिल रहा सैनिटरी पैड

- अब तक 105+ करोड़ सैनिटरी पैड कराए गए उपलब्ध
- मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार
- संक्रमण व बीमारियों से सुरक्षा

12 वर्षों के सुशासन का प्रभाव

1. लिंगानुपात (जन्म के समय)
2. उच्च शिक्षा में महिला नामांकन
3. संस्थागत प्रसव
4. शौचालय कवरेज
5. स्वयं सहायता समूह सदस्यता
6. मातृ मृत्यु दर
7. सुरक्षा बलों में महिला अधिकारी
8. पेड मैटरनिटी लीव

2014*	2026*
918	929
9.86 लाख	34+ लाख
68%	98%
39%	100%
2.35 करोड़	10+ करोड़
130	80
3,000	11,000+
12 सप्ताह	26 सप्ताह

*आधार वर्ष, योजना की शुरुआत या अन्य कारणों से आंकड़ों में अंतर हो सकता है

जब महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ती है, तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद होती जाती है। इसलिए, सुविधा और सुरक्षा का विश्वास देने के साथ-साथ हमने बहनों की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया है। हमारी सरकार की नीतियों में निरंतर महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रगति पथ पर अग्रसर...

12 वर्ष की यात्रा

महिलाओं के हाथ में है स्टार्टअप्स की कमान

डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त

48% स्टार्टअप्स में है महिला निदेशक

3+ लाख

महिलाओं को शक्ति सदन और 5+ लाख को सखी निवास का मिला लाभ

12+ करोड़

शौचालयों का निर्माण- सुनिश्चित हो रहा **गरिमामय जीवन और सम्मान**

मिशन इंद्रधनुष के तहत

5.4+ करोड़

बच्चों और **1.3+ करोड़** गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, सुरक्षित हुआ जीवन

1000+ वन स्टॉप सेंटर और 24x7 महिला हेल्पलाइन से मिल रही मदद

700+ फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें महिलाओं को कर रहीं त्वरित न्याय प्रदान

डिजिटल साक्षरता से खुल रहा अवसरों का नया आसमान, **पीएमजीदिशा** के तहत लगभग

6.4 करोड़

लोग किए गए प्रशिक्षित

लगभग **3.6 करोड़** महिलाओं को मिली डिजिटल साक्षरता

जल जीवन मिशन
से लगभग

16 करोड़ घरों को मिल रहा नल से शुद्ध जल

- दूरदराज से पानी लाने की पीड़ा से मुक्ति
- समय की होने लगी बचत
- शुद्ध जल मिलने से स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ी
- जल जीवन मिशन की समितियों में महिलाओं की बड़ी भूमिका

वैश्विक मंच पर लहराया नारी शक्ति का परचम, विश्व का सबसे बड़ा महिला शांति दल भारत ने किया तैनात

1.15 करोड़

किशोरियों के लिए मुफ्त एचपीवी टीकाकरण अभियान

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए 'भारतीय न्याय संहिता' में सख्त प्रावधान

- शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे या पहचान प्रकट करने आदि की धमकी देकर यौन संबंध बनाने को एक नए अपराध की श्रेणी में शामिल किया
- अब गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान
- बच्चों से अपराध कराने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम सात से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान
- 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में दुष्कर्म पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया

SHE-बॉक्स पोर्टल

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायतों के लिए डिजिटल मंच

नव्या योजना: 16-18 वर्ष की किशोरियों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण

SHE-Marts: ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए विपणन प्रणाली मजबूत करने की पहल

स्वस्थ नारी अभियान

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण हेतु राष्ट्रीय अभियान

अध्याय 2

सशक्त युवाः विकसित भारत के सारथी

12 + करोड़

नए उद्यमियों को

पीएम मुद्रा योजना

में लोन, युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान

- बिना गारंटी के ₹ 20 लाख तक लोन
- शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस की चार श्रेणियों में सुविधा
- छोटे व्यापार, दुकान, स्टार्टअप को नई शुरुआत
- बैंकिंग सिस्टम से जुड़ाव बढ़ा
- "जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर" बनाने की दिशा में सशक्त क़दम

युवा शक्ति + शासकीय सहयोग = नए भारत की नई शुरुआत

योजनाओं से युवा हो रहे सशक्त

60 + लाख

युवाओं को मिला

पीएम विकसित भारत रोजगार योजना

का लाभ

- नियोजकों को **EPFO** में 2 साल तक सब्सिडी- नियुक्ति आसान
- पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को विशेष प्रोत्साहन
- युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति
- 60 लाख घरों में खुशहाली - विकसित भारत की झलक

₹1 लाख करोड़ की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से

3.5 करोड़ नए रोजगार

होंगे सृजित, युवाओं के लिए खुल रहे तरक्की के द्वार

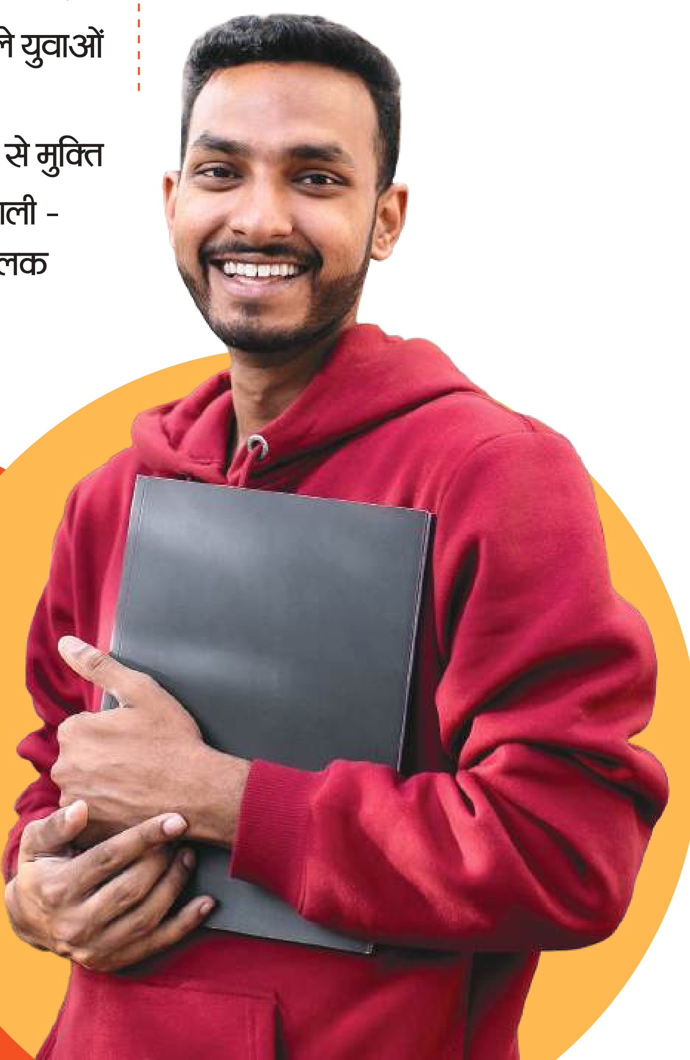

63,000+

खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स में हुए शामिल, युवा प्रतिभाओं को मिल रहा नया मंच

300+ खिलाड़ियों को TOPS योजना से मिल रहा विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सहयोग

107

पदक जीतकर भारत ने एशियाई खेल 2022 में रचा इतिहास

1+ करोड़

स्कूली छात्र

10,000+ अटल टिंकरिंग लैब से प्रशिक्षित

नवाचार, विज्ञान और तकनीक से जुड़े

- "सोचो, बनाओ, सीखो" की संस्कृति विकसित
- किताबों से हटकर छात्रों में नवाचार एवं समस्या समाधान उन्मुखी मानसिकता
- देश को मिल रहे भविष्य के आविष्कारक और वैज्ञानिक
- सरकारी स्कूलों में विश्वस्तरीय सुविधा

1.6+ करोड़

युवाओं को

पीएम कौशल विकास योजना से प्रशिक्षण

कुशल युवा देश की तरक्की का आधार

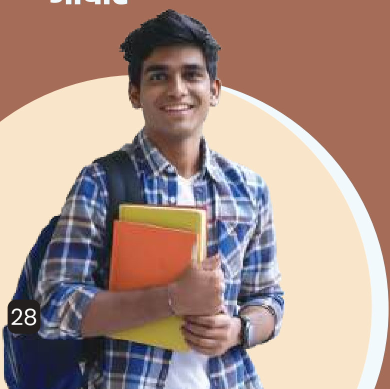

- मुफ्त कॉमर्शियल ट्रेनिंग की सुविधा
- आईटी, निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, फैशन सहित 200+ कोर्स
- शासकीय प्रमाणपत्र - देशभर में मान्य
- कम पढ़े-लिखे युवाओं को भी हुनर की पहचान
- कुशल कार्यबल से उत्पादकता में वृद्धि
- मेक इन इंडिया के लिए कुशल मानव संसाधन हुआ आसान

12+ लाख

नियुक्ति पत्र रोजगार मेलों
के माध्यम से वितरित, रोजगार का सपना हो रहा साकार

- परीक्षा पास करने के बाद लंबे इंतजार का अंत
- केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्ति
- पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त नियुक्ति प्रक्रिया

1+ करोड़

एसटी छात्रों को
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
उज्ज्वल भविष्य की राह हो रही आसान

- 10वीं के बाद उच्च शिक्षा जारी रखने का अवसर
- कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, इंजीनियरिंग तक सीधी पहुँच
- ड्रॉपआउट दर में कमी, आदिवासी बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा
- गरीब जनजातीय परिवारों पर शिक्षा का बोझ शून्य

पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का बढ़ता प्रभाव

1. विश्वविद्यालय
2. कॉलेज
3. उच्च शिक्षा नामांकन
4. एम्स
5. आईआईटी
6. लड़कियों के लिए अलग शौचालय वाले स्कूल
7. बेरोजगारी दर
8. स्टार्टअप
9. रोजगार संख्या
10. पैरालिंपिक पदक

2014*	2026*
723	1,338
36,634	52,081
3+ करोड़	लगभग 4.5+ करोड़
8	23
16	23
9+ लाख	14+ लाख
6.1%	3.2%
350	2.2 लाख
45.5 करोड़ (2017-18)	60+ करोड़ (2023-24)
31 (1960-2020)	29 (2024)

*आधार वर्ष, योजना की शुरुआत या अन्य कारणों से आंकड़ों में अंतर हो सकता है

भारत के युवाओं का ध्यान वास्तविक समस्याओं के समाधान पर है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने नए सपने देखने का साहस किया है।

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रगति पथ पर अग्रसर...

12 वर्ष की यात्रा

लगभग **13 लाख** नौकरियां, **पीएलआई योजनाओं** से **₹2+ लाख करोड़** निवेश

अब देश में

2,100+

मेडिकल कॉलेज,

सुनिश्चित हो रहीं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं

एमबीबीएस यूजी सीटें 1,28,976 और पीजी सीटें 85,822 हुईं

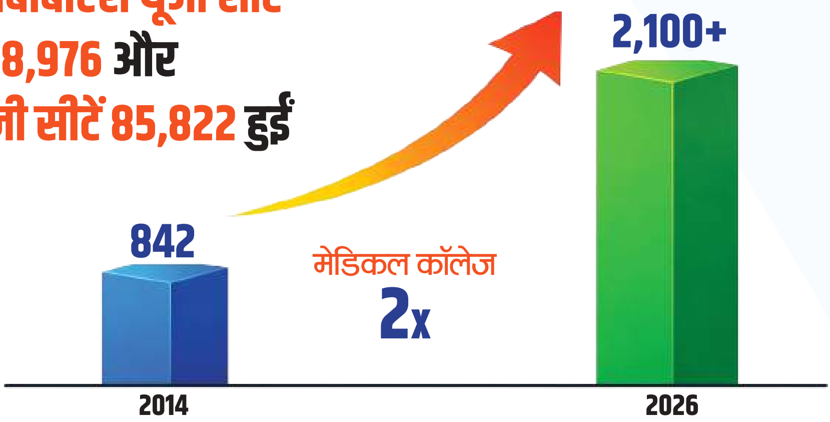

2.2 लाख

स्टार्टअप्स से मिली

23+ लाख नौकरियां

1.5 लाख

अग्निवीरों की हुई भर्ती, सुरक्षित और समृद्ध भारत का मजबूत आधार

16+ लाख

नवाचार परियोजनाएं छात्रों द्वारा विकसित, **स्टार्टअप इकोसिस्टम** को मिल रही मजबूती

728

एकलव्य मॉडल स्कूलों से जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य

₹18.5 लाख करोड़

का वित्त वर्ष 2024-25 में **आईटी और आईटीईएस क्षेत्र** से निर्यात

पीएम-सेतु योजना

1,000 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए
₹60,000 करोड़

औद्योगिक कॉरिडोर के पास **पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप** का हो रहा विकास, युवाओं के लिए नए अवसरों का बन रहा आधार

20+ लाख

नए सदस्य, मई 2025 में **ईपीएफओ** में जुड़े, बढ़ता रोजगार तरक्की का आधार

600+
ग्रामीण क्षेत्र
के स्कूलों में स्थापित हुईं
1,200+ व्यावसायिक कौशल लैब

23+ करोड़

युवाओं की भागीदारी

फिट इंडिया कार्यक्रमों

ने दिया मंच

राष्ट्रीय खेल नीति 2025

भारत को 2036 ओलंपिक तक

वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दिशा में दे रही नई गति

अध्याय 3

समर्थ किसान, समृद्ध राष्ट्र

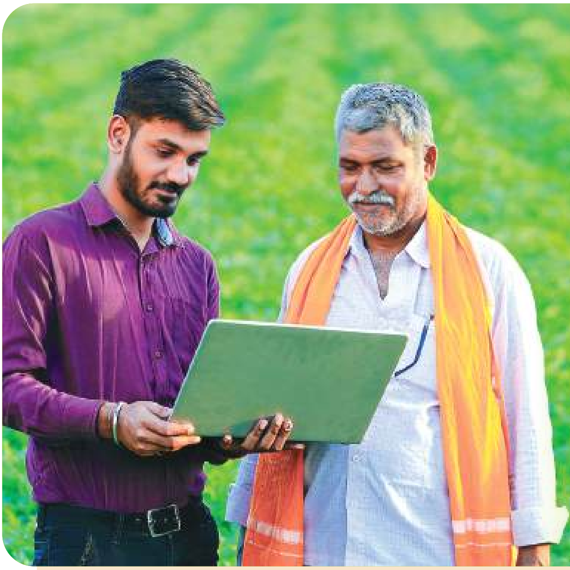

लगभग

₹5

लाख करोड़ की फसल बिक्री **e-NAM प्लेटफॉर्म** पर, 1.8+ करोड़ किसानों को मिला नया बाजार

- बिचौलियों से मुक्ति - 1,656 मंडियों से सीधा जुड़ाव
- घर बैठे फसल की बोली - समय व पैसे की बचत
- छोटे व सीमांत किसानों को बड़े बाजार की ताकत
- 'अन्नदाता' को मिला तकनीक का साथ

25 मेगा फूड पार्क ऑपरेशनल

सुरक्षित हो रही किसानों की फसल, मिल रहे बेहतर दाम

- 41 मेगा फूड पार्क को स्वीकृति
- किसानों को मिलेगा उचित मूल्य
- कृषि से जुड़े क्षेत्रों को भी होगा फायदा

बीज से बाजार तक किसानों के साथ सरकार

₹4.3+ लाख करोड़

का कृषि, समुद्री एवं खाद्य निर्यात 2025-26 में हुआ 2013-14 की तुलना में हुई एक तिहाई की वृद्धि

- भारतीय किसानों के उत्पाद को विश्व बाजार में मिली नई पहचान
- निर्यात बढ़ने से किसानों का हो रहा सशक्तीकरण

₹4+ लाख करोड़

की आर्थिक सहायता किसानों को **पीएम-किसान सम्मान** निधि से मिली

- आर्थिक सहायता मिलने से खेती हुई आसान
- बुवाई से कटाई तक सभी जरूरतों की पूर्ति

12,800+ एग्री स्टार्टअप

कृषि क्षेत्र में भारत कर रहा है परिवर्तनकारी नवाचार

4+ करोड़ किसानों को मिला पीएम फसल बीमा योजना का लाभ, किसानों का जीवन हुआ सुरक्षित

- 2016-2025 के बीच लगभग ₹2 लाख करोड़ दिए गए
- प्रीमियम कम कर कवरेज बढ़ाया
- जंगली जानवर द्वारा किया गया नुकसान अब स्थानीय नुकसान में कवर
- किसानों को प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षा

लगभग

8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को मिल रही वित्तीय सहायता, जीवन हो रहा आसान

- विश्वसनीय लोन इकोसिस्टम से किसान सशक्त
- खेती से जुड़ी गतिविधियों और फसल कटाई के बाद की आवश्यकताओं में मिल रही सहायता

किसानों के विकास को समर्पित 12 वर्ष

1. कृषि निर्यात
2. बागवानी उत्पादन
3. फूड प्रोसेसिंग
4. प्रोसेस्ड फूड का निर्यात
5. मेगा फूड पार्क स्वीकृत
6. एग्री स्टार्टअप

2014*	2026*
₹3.57 लाख करोड़	₹4.89 लाख करोड़
2,807 लाख टन	3,690 लाख टन
₹1.34 लाख करोड़	₹2.24 लाख करोड
13.7%	20.4%
2	41
0	11,000+

*आधार वर्ष, योजना की शुरुआत या अन्य कारणों से आंकड़ों में अंतर हो सकता है

भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। हम इनसे संबंधित किसी भी हानिकारक नीति के खिलाफ दीवार की तरह खड़े हैं।

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रगति पथ पर अग्रसर...

12 वर्ष की यात्रा

एग्रीश्योर फंड से

₹750 करोड़ की ब्लेंडेड कैपिटल से कृषि एवं ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा

तकनीक आधारित कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा

10,000

किसान उत्पादक संगठन सामूहिक उद्यमी बने

21+ लाख किसान

पीएम-कुसुम योजना से बने ऊर्जा उत्पादक

पीएम मत्स्य संपदा योजना

से मछली उत्पादन दोगुना

2014-15 में 0.95 करोड़ टन से बढ़कर अब लगभग **2 करोड़ टन** हुआ

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन

से शहद उत्पादन और निर्यात में वृद्धि

लगभग

1.70 **लाख परियोजनाएं**

कृषि अवसंरचना कोष के तहत स्वीकृत

आत्मनिर्भर दलहन मिशन

₹11,440 करोड़

होंगे खर्च

350 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य

उच्च उत्पादकता बीज मिशन

सीड्स एंड प्लांटिंग मैटेरियल कार्यक्रम के तहत **6.85 लाख** बीज गांव विकसित, लगभग **16,450 लाख क्विंटल** गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन

कपास उत्पादकता मिशन

के लिए लगभग **₹5,660 करोड़**, किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और उन्नत खेती का लाभ

फल एवं सब्जी कार्यक्रम

फल एवं सब्जियों का निर्यात ₹15,000+ **करोड़** तक पहुंचा, बागवानी क्षेत्र की वैश्विक बाजार में मजबूत भागीदारी

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना

मखाना क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ₹470+ करोड़ की केंद्रीय स्कीम

Bharat Vistaar

भारत-विस्तार

क्षेत्रीय भाषा में एआई आधारित कृषि सलाह मंच

10+ केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और स्थिति एक ही प्लेटफॉर्म पर

अध्याय 4

वंचितों का विकास, राष्ट्र की सशक्त धारा

2 + लाख

कार्यक्रमों का जनजातीय गौरव वर्ष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन

- जनजातीय संस्कृति और विरासत को मिला सम्मान

जनजातीय गौरव को मिल रही नई पहचान

11

नए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मिली स्वीकृति, **जनजातीय नायकों की वीरता** को सम्मान

- गुमनाम नायकों को अमृत महोत्सव वर्ष से मिली पहचान
- अब जनजातीय इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर
- भारत का प्राचीन गौरव अब संग्रहालय के माध्यम से भावी पीढ़ी से जुड़ रहा है

53 + लाख

असंगठित श्रमिकों का **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना** में पंजीकरण

- सुनिश्चित हुई सामाजिक सुरक्षा, मिला सरकारी योजनाओं का लाभ

पीएम फसल बीमा योजना

किसानों को सरल, किफायती और व्यापक फसल बीमा समाधान

71%

लाभार्थी SC/ST/OBC किसान

पीएम-किसान योजना के

80%

लाभार्थी छोटे एवं सीमांत किसान, मिली आर्थिक सुरक्षा, जोखिम से मिली निजात

58%

छात्रवृत्ति के लाभार्थी हैं **SC/ST/OBC समुदाय**, शिक्षा से हो रहा सशक्तीकरण और सामाजिक बदलाव

पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत

44.2%

घर **SC/ST** समुदायों को किए प्रदान, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की नई उड़ान

34 लाख

दिव्यांगजनों को लगभग 20,300 शिविरों से मिली सहायता और सुविधाएं, दूर हुईं चिंताएं

1.36 करोड़ ई-यूडीआईडी कार्ड जारी

- यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एकल और यूनिवर्सल पहचान पत्र है
- करीब 8 लाख कार्ड अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के
- 1 अप्रैल 2024 से सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सब्सिडी और रोजगार के अवसरों का लाभ लेने के लिए अनिवार्य
- कई अलग-अलग दस्तावेज की आवश्यकता समाप्त, सर्विस डिलीवरी हुई अधिक प्रभावी
- डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था

दिव्यांगजन कौशल योजना

से दिव्यांगजनों को आईटी और एवीजीसी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण, सम्मानजनक रोजगार का सपना हो रहा साकार

दिव्यांग सहारा योजना

आधुनिक सहायक उपकरण और एआई आधारित नवाचार से दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को मिला सम्मानजनक जीवन

सुगम्य भारत ऐप

दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल सहायता मंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में सरकारी रोजगार में बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए न्यूनतम 4% आरक्षण, पदोन्नति में 4% आरक्षण अनिवार्य

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए

स्माइल योजना

- शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सहायता
- स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास और आश्रय सहायता
- ट्रांसजेंडर समुदाय का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण

ट्रिपल तलाक मामलों में आई

82%

की कमी

12 वर्षों के सुशासन का प्रभाव

ओबीसी/ईबीसी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

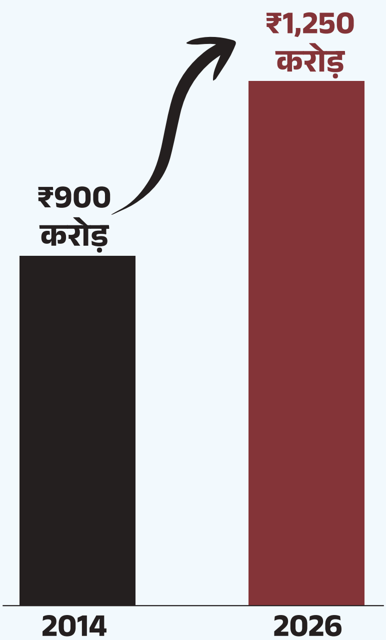

- **अब केवल 'दिव्यांग' कहिए, विशिष्टता-दिव्यता का संदेश**

ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति

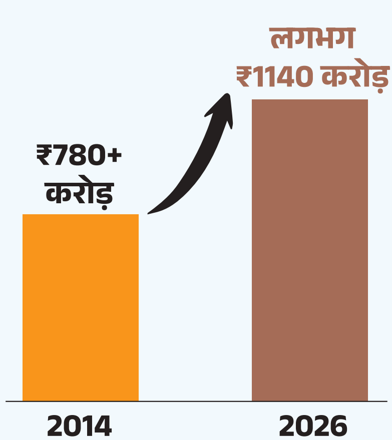

- 2026 में एससी छात्रों को लगभग ₹560+ करोड़ की छात्रवृत्ति की गई प्रदान
- दिव्यांग श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़कर 21 हुई

एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

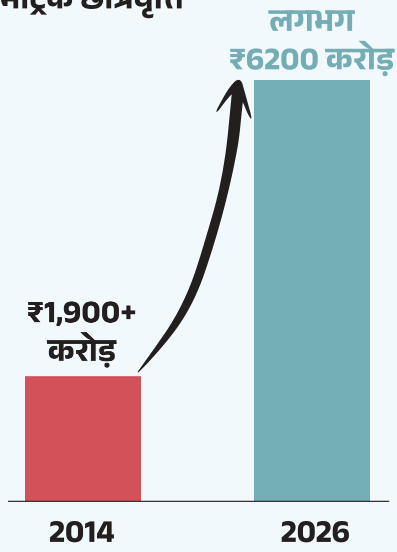

सामाजिक न्याय मंत्रालय बजट

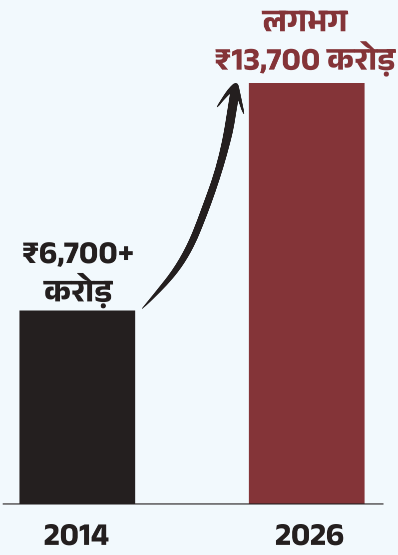

*आधार वर्ष, योजना की शुरुआत या अन्य कारणों से आंकड़ों में अंतर हो सकता है

विकास सर्वांगीण होना चाहिए, विकास सर्वव्यापी होना चाहिए, विकास सभी को शामिल करने वाला होना चाहिए।

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रगति पथ पर अग्रसर...

12 वर्ष की यात्रा

लगभग **2 लाख** लोगों को **पीएम-दक्ष योजना** से मिला कौशल प्रशिक्षण

पीएम विश्वकर्मा योजना

से पारंपरिक कारीगरों को सहायता

499

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ऑपरेशनल, 728 का लक्ष्य, 723 को मंजूरी

- 1.5 लाख से अधिक छात्र इन स्कूलों में ले रहे हैं शिक्षा
- 15 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं नए एकलव्य स्कूल
- 6-12वीं तक के आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की प्रमुख पहल
- सभी विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम और शैक्षिक मानक
- **IIT**, **NEET** आदि जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन ट्यूशन
- छात्रों को भविष्य में करियर संबंधी अवसरों के लिए विशेष प्रशिक्षण

पीएम जनमन

के तहत जनजातीय समूहों को **उद्यमिता प्रशिक्षण**

गिग और प्लेटफॉर्म

श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा

10%

सवर्ण आरक्षण, उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के सपनों की मिली नई उड़ान

63,000+

गांवों और **5+ करोड़ आदिवासियों** को **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान** से मिले शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार

मुद्रा योजना

57 + करोड़ लोन

योजना में **49% लोन SC/ST/OBC लाभार्थियों** को मिले, सामाजिक सशक्तीकरण और स्वरोजगार की राह हुई आसान

5

लाख SC/ST महिला उद्यमियों को **2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए

10%

आरक्षण

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY)

अनुसूचित जाति बहुल गांवों में कौशल, रोजगार और आजीविका को मिला बढ़ावा, हो रहा सामाजिक विकास

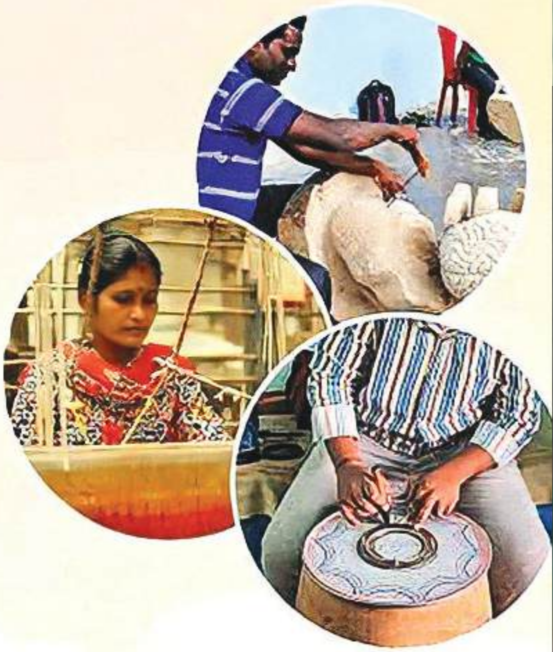

पीएम केयर्स योजना

से ओबीसी छात्रों को मुफ्त कोचिंग सुविधा, प्रतिभा को मिला अवसरों का नया आसमान

PM CARES

Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund

सत्यमेव जयते

> मैंने भारत के कोने-कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए शरीर का कण-कण, जीवन का क्षण-क्षण, आप सबकी सेवा में समर्पित है। और भारत को विकसित बनाने के लिए चार सबसे बड़ी प्राथमिकता है- गरीब, किसान, नौजवान और नारीशक्ति। ये चारों सशक्त हो गए, तो हर समाज, हर वर्ग, देश का हर परिवार सशक्त हो जाएगा।

— नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

मुद्रक: चन्द्र प्रभु ओफसेट प्रिंटिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा